साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 26 मई से 01 जून 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 07 में...
गिल को तीन चुनौतियाँ

पेज 12 में...
झीरम की 12वीं बरसी

वर्ष : 01 अंक : 12 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 03 सुशासन से आई जमीन रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियां...

महकमा मालामाल सड़कें लहूलुहान...

- प्रदेश में पिछले चार महिनों में 5322 सड़क दुर्घटना में 2591 की मौत
- छत्तीसगढ़ की सड़कों में सिर्फ 4 माह में 2591 की मृत्यु, 4825 घायल

- परिवहन विभाग ने 2 लाख 80 हजार 568 प्रकरणों में 58.35 करोड़ वसूला
- पुलिस विभाग ने 3 लाख 06 हजार 106 मामलों में कमाया 11.92 करोड़

दुर्घटना रोकने कार्ययोजना बनाने में अफसर अव्वल, क्रियान्वयन में सभी दोयम

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में हादसों को रोकने के लिए एक दफा फिर परिवहन और यातायात समेत पूरा पुलिस महकमा एसी हॉल में उठक-बैठक कर रहा है। शुक्रवार को एसीएस मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अनुभवी आला अफसरों ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए खासी माथापच्ची कर कार्ययोजना बनाई है। लेकिन इन लंबी चौड़ी कार्ययोजना का क्रियान्वयन कब तक होगा यह अभी पाइप लाइन में है। प्रदेश में पिछले चार महिनों में 5322 सड़क दुर्घटनाओं में 2591 व्यक्ति की मृत्यु एवं 4825 घायल हुए हैं। परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

वहीं एसीएस मनोज पिंगुआ कहते हैं हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों का सबकी सहभागिता से बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जनजागरूकता के लिए बाकायदा कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषयक पाठों शामिल किया जायेगा। प्रदेश के 8 जिलों के दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों को भी चिन्हांकित करने और सुधार के लिए योजना बनाई गई है। बता दें कि पूर्व में भी राज्य निर्माण से लेकर अब तक हादसों की रोकथाम के लिए कई योजना बनीं लेकिन बेहतर क्रियान्वयन नहीं होने से सब बेकार साबित हुई।

ब्लैक स्पॉट वाले जिले

- रायपुर
- बिलासपुर
- दुर्ग
- कोरबा
- रायगढ़
- बलौदाबाजार
- सरगुजा
- जगदलपुर(बस्तर)

चार महीने में इतनी मौत, घायल और जुर्माना

परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने विभागीय गतिविधियों के संबंध में बताया कि प्रदेश में पिछले चार महिनों में 5322 सड़क दुर्घटनाओं में 2591 व्यक्ति की मृत्यु एवं 4825 घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सचिव श्री एस प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2019-2025 तक चिन्हाकित/लंबित ब्लैक स्पॉट्स में से 69 तथा 101 जंक्शन सुधार किया गया है।

हादसे होते रहे शुल्क वसूली चलती रही

यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा 3 लाख 06 हजार 106 प्रकरणों में 11.92 करोड़ रूपए तथा परिवहन विभाग द्वारा 2 लाख 80 हजार 568 प्रकरणों में 58.35 करोड़ रूपए की शमन शुल्क वसूल किए गए है।

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

जब सड़क हादसों में किसी का सुहाग, किसी की गोद और किसी का पूरा परिवार उजड़ रहा था तब परिवहन और यातायात विभाग जुर्माना वसूली में मशगूल था। प्रदेश की सड़कें लहूलुहान होती रहीं और 28 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी वातानुकूलित कमरे में बैठकर हादसों की रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाते रहे। कार्ययोजना बनाने में अव्वल और उसके क्रियान्वयन में दोयम दर्जा हासिल परिवहन अफसर अब भी पिछले चार माह में मौत और घायलों के आंकड़ों के साथ ही परिवहन नियमों से वसूली गई जुर्माना राशि के हिसाब-किताब में लगे हुए हैं। उनकी नाक के नीचे हादसों में अकाल मौत और गंभीर घायल निःशक्त होते जा रहे हैं फिर भी उनमें बेफिक्री का आलम है। अब नया शिगूफा चर्चा में है पहली से कक्षा 10वीं तक रोड ट्रैफिक विषय पाठ्यक्रम में पढ़ाया जायेगा। सवाल यह उठता है कि क्या स्कूली बच्चे ट्रक, मालवाहक, तेज रफ़्तार बाइक और कार चलाते हैं जिन्हें यह पढ़ना जरुरी है ?

साप्ताहिक शहर सत्ता

कार्ययोजना सहीं, क्रियान्वयन नहीं

सड़क दुर्घटनाओं पर समस्त जिला अस्पतालों में सातों दिन चौबीसों घंटे एक्सरे, लेबोट्री जांच, इमरजेंसी संबंधित आवश्यक दवाईयां, इन्जेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किये गए हैं।

अफसर बताते हैं ऐसे रुकेगा हादसा

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सड़क सुरक्षा उपायों का सबकी सहभागिता से बेहतर क्रियान्वयन होन आवश्यक है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात को बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास किया जाना जरुरी है।

मनोज पिंगुआ, एसीएस छग. शासन

विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वर्ष 2019-2025 तक चिन्हाकित/लंबित ब्लैक स्पॉट्स में से 69 तथा 101 जंक्शन सुधार किया गया है। यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई भी तेज की गई है।

एस प्रकाश, सचिव छग. परिवहन विभाग

आगामी शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रमों मे सड़क सुरक्षा विषयक पाठों के लागू करने से हादसों को रोका जा सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों में रोड़ क्लब गठित कर नियमित गतिविधियों से सड़क सुरक्षा का वातावरण तैयार किया जायेगा। दोपहर 03 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे के मध्य शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही है। इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक दोपहिया वाहन चालक/सवारों की मृत्यु की प्रमुख वजह बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना है।

संजय शर्मा, अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा)

इनकी हो मॉनिटरिंग

- हिट एण्ड रन प्रकरणों के प्रभावितों को राहत के लिये गठित जिम्मेदार लेटलतीफ
- ग्रामीण-शहरी इलाकों में दोपहर 03 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे के बीच हादसे ज्यादा
- बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइव पर परिवहन-यातायात की कार्रवाई कमतर
- सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावितों के धनरहित उपचार में क्रियान्वयन में कई खामियां
- जिला अस्पतालों में सातों दिन चौबीसों घंटे सेवा उपलब्ध करने का एलान सिर्फ प्लान

7.19 लाख हुए 1234 प्रोग्राम से जागरूक

इस वर्ष शाला सुरक्षा प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात जागरूकता के 1234 कार्यक्रमों में 7,19,000 लाभान्वित हुए है। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा में स्वास्थ्य सेवाएं, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शिक्षा, परिवहन, सामान्य प्रशासन विभागों में कार्यरत योग्य व सेवानिवृत अधिकारियों की भी सहभागिता के बाद भी दुर्घटना नहीं रुकी। इसी कड़ी में 5388 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।

इतने विभाग-अफसरों की रायशुमारी

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, एन.आर.डी.ए. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार सहित स्वास्थ्य सेवायें, गृह, पंचायत, वित्त, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिवहन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खनिज, उर्जा, जनसंपर्क, खाद्य, पर्यावरण, आबकारी, कृषि, श्रम, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, वित्त, पशुपालन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, समस्त संभाग आयुक्त, तथा पुलिस महानिरीक्षक रेंज, सर्वाधिक सड़क दुर्घटना के जिला कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षक ने की चर्चा।

मौत और दुर्घटना की ये है वजह

शैक्षणिक संस्थानों में रोड़ क्लब गठित कर नियमित गतिविधियों से सड़क सुरक्षा का वातावरण तैयार करने कार्ययोजना बनी। प्रदेश में दोपहर 03 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे के मध्य शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही है। इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक दोपहिया वाहन चालक/सवारों की मृत्यु की प्रमुख वजह बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना है।

हादसा रोकने रौशनी का खास इंतजाम

प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में 3,72,406 एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाये गये है। इसके अलावा 1,02,410 अतिरिक्त लाईट्स की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़के पशु मुक्त न होने से, अवैध साईन बोडर्स के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही न होने से हो रही सड़क दुर्घटनाएं।

सड़कें लाल, खून से लथपथ

1. रायपुर-बलौदा बाजार मार्ग पर भीषण हादसा (12 मई 2025)
रायपुर जिले के सारा गांव के पास एक ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। यह हादसा रात में हुआ जब परिवार के सदस्य एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे।

2. महासमुंद में कार-ट्रक टक्कर (25 मई 2025)
महासमुंद जिले के कोडार डैम के पास एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे एक बुजुर्ग दंपति और एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे का कारण ट्रक का बिना चेतावनी संकेत के खड़ा होना बताया गया है।

3. रायपुर में महिला की ट्रक से कुचलकर मौत (16 मई 2025)
रायपुर के तेलीबांधा चौक पर एक 26 वर्षीय महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई।

4. सक्ती जिले में सड़क हादसा (मई 2025)
सक्ती जिले में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की।

5. रायपुर में महिला की ट्रक से कुचलकर मौत (16 मई 2025)
रायपुर के तेलीबांधा चौक पर एक 26 वर्षीय महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई।

6. रायपुर में महिला की ट्रक से कुचलकर मौत (16 मई 2025)
रायपुर के तेलीबांधा चौक पर एक 26 वर्षीय महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई।

7. रायपुर में महिला की ट्रक से कुचलकर मौत (16 मई 2025)
रायपुर के तेलीबांधा चौक पर एक 26 वर्षीय महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई।

8. रायपुर में महिला की ट्रक से कुचलकर मौत (16 मई 2025)
रायपुर के तेलीबांधा चौक पर एक 26 वर्षीय महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई।

दर्दनाक मौत का ये निशान

आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, जमीन रजिस्ट्री के साथ-साथ अब सुरक्षित नामांतरण

सुशासन से आई जमीन रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियां

शहर सत्ता/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दूरदर्शी सोच के अनुरूप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी. चौधरी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रदेश में "रजिस्ट्री की 10 क्रांतिकारी प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं, जिससे आमजन विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा। मंत्री देवांगन ने कहा कि समस्त प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित हों और फर्जीवाड़ा जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके इसलिए सभी सुरक्षित और सुलभ तरीके से प्रक्रिया का डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है।

जमीन रजिस्ट्री में यह हैं 10 नई क्रांति

फर्जी रजिस्ट्री रोकने सत्यापन

पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड व बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नही हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार नही होना पड़ेगा और फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

रजिस्ट्री खोज डाउनलोड सुविधा

आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते है, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से

उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, रजिस्ट्री खोज का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी।

ऑनलाइन भारमुक्त सर्टिफिकेट

भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है जो संपत्ति खरीदने के पूर्व उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा।

कैशलेस भुगतान

पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग-अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एक साथ सुविधानुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई से फीस का भुगतान हो सकेगा।

व्हाट्सएप सेवा

व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी।

डिजीलॉकर की सुविधा

रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पडऩे पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।

रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण

जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा।

घर बैठे स्टाम्प दस्तावेज बनेंगे

डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किए जा सकते हैं।

घर बैठे रजिस्ट्री

दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे-रेंट एग्रीमेंट, मोर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है।

रजिस्ट्री और नामांतरण

रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी।

अब तक अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराने के बाद उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता रहा हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए भटकना पड़ता था। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार भी नही होना पड़ेगा।

आयुष्मान और वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर

3 लाख 60 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पीएम आयुष्मान वय-वंदना योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निः शुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ मे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 3 लाख 60 हजार से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय-वंदना कार्ड बन चुके हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में पांचवें स्थान पर पहुँच गया है। इस मामले में राज्य ने राजस्थान, महाराष्ट्र , ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से आगे निकलकर कीर्तिमान रच दिया है।

- **राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार से बेहतर स्थिति में है छत्तीसगढ़**

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर लगातार आयुष्मान वय-वंदना कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिससे कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक योजनांतर्गत् निःशुल्क इलाज लाभ पाने से वंचित ना रह जाए। जिलों में आयुष्मान वय-वंदना पंजीयन हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के अतिरिक्त, सामाजिक संस्थाओं, पेंशनर संथाओं, शियान-सदन, वरिष्ठ-जन कल्याण संघों, वृद्धाश्रमों, निजी आवासीय सोसायटियों, इत्यादि से लगातार संपर्क कर शिविर लगाए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि, कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता या अन्य सदस्य यदि 70 वर्ष व अधिक आयु के हैं एवं उनके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो वे नजदीकी शासकीय चिकित्सालय, सी.एम.एच.ओ./ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या शासकीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या टोल फ्री टेलीफोन नंबर 104 पर बात कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। व्यक्ति चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान भारत एप व आधार फेस आई.डी. एप डाउनलोड कर आधार वेरीफिकेशन से अपना सामान्य आयुष्मान कार्ड या घर के वरिष्ठ सदस्य का आयुष्मान वय-वंदना कार्ड दोनों पंजीयन स्वयं भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि माह अक्टूबर 2024 से देश में प्रारंभ वय-वंदना कार्ड पंजीयन में राज्य में नवंबर के बाद तेजी से कार्य किया जा सका है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से गर्भवती महिलाओं को मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

रायपुर। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में राज्य के समस्त जिलों में अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच व उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान की जा रही है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (High Risk Pregnancy - HRP) की पहचान और समुचित प्रबंधन व चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस अभियान के प्रभावस्वरूप छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004-06 में राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 335 प्रति एक लाख जीवित जन्म था, जो अब घटकर 132 पर आ गया है। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी राष्ट्रीय औसत (93) से अधिक है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस दिशा में और अधिक ठोस और योजनाबद्ध प्रयासों की रूपरेखा तैयार की है।

जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के अंतर्गत कुल 800 से अधिक सत्रों का सफल आयोजन किया गया। इन सत्रों में से 360 PMSMA सत्रों की निगरानी राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से की गई तथा आयोजित सत्रों के दौरान लगभग 30 हज़ार गर्भवती महिलाओं ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। इनमें से लगभग 9000 से अधिक महिलाएं उच्च जोखिम गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेग्नेंसी) की श्रेणी में चिन्हित की गईं, जिन्हें विशेष चिकित्सकिया देखभाल प्रदान किया गया । गौरतलब है कि अधिकांश मातृ मृत्यु के पीछे उच्च जोखिम गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं प्रमुख कारण हैं। ऐसे में समय रहते H R P की पहचान, उचित उपचार एवं सतत निगरानी अभियान के प्रमुख उद्देश्य बनाए गए हैं। इस संदर्भ में राज्य के समस्त जिलों में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कलेक्टरों द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ-साथ मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा, "हर गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार है, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इस दिशा में एक सशक्त एवं प्रभावी कदम है।

बीजापुर में तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा पूरा मेहनताना

रायपुर। बीजापुर जिले में इस वर्ष 1,21,600 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संग्रहण कार्य 9 मई 2025 से प्रारंभ हुआ था और 21 मई तक कुल 12,226.638 मानक बोरा का संग्रहण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बीजापुर ने बताया है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके परिश्रम का पूरा मूल्य उन्हें समय पर और सुरक्षित रूप से मिलेगा।

प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बीजापुर ने स्पष्ट किया है कि यह नुकसान संग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण हुई इस क्षति के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। सभी संग्राहकों को उनके मेहनताना की पूरी राशि उनके बैंक खातों में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि समिति देपला के फड़ कोत्तागुड़ा, गोरगुंडा-अ$ब, पोषडपल्ली, कारकावाया एवं समिति चेरपल्ल्ी के लॉट क्रमांक 12 अ चेरपल्ली के फड़ चिल्लामरका का संग्रहित तेंदूपत्ता की गड्डियां नदी किनारे सुखाई जा रही थी और 22 मई की रात हुई बेमौसम बारिश और 23 मई को नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण तेंदूपत्ता की 4,60,840 गड्डियों में से 3,23,539 गड्डियां तेज बहाव में बह गईं। इससे लगभग 17.79 लाख रूपए की तेंदूपत्ता क्षतिग्रस्त हुई।

साप्ताहिक शहर सत्ता

तेंदूपत्ता पर मौसम की मार 90 करोड़ रुपये का नुकसान

आंधी, ओले और बारिश ने बिगाड़ी संग्राहकों की कमाई

शहर सत्ता/ जगदलपुर। बस्तर में "हरा सोना" कहे जाने वाले तेंदूपत्ते की फसल इस साल तेज हवाओं और ओलों की मार के कारण पूरी तरह प्रभावित हुई है। ये पत्ते उनके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत हैं। कई संग्राहकों का कहना है कि बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। तेंदूपत्ता संग्रहण पर मौसम का असर अब केवल वन उत्पादों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हजारों ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। यदि यही स्थिति रही, तो आने वाले वर्षों में संग्रहण लक्ष्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

संग्राहकों के मुताबिक बस्तर संभाग में आंधी, ओले और बारिश के कारण तेंदूपत्ता संग्रहण लक्ष्य से पीछे रह गया, जिससे संग्राहकों को लगभग 90 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है।

संग्रहण लक्ष्य से पीछे, नुकसान में हजारों संग्राहक

बस्तर संभाग में इस वर्ष 2 लाख 70 हजार 600 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब तक 101057 संग्राहकों द्वारा केवल 1 लाख 16 हजार 999 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण ही हो सका है। यानि लक्ष्य की तुलना में करीब 57% ही संग्रहण हो पाया है। इससे अब तक केवल 64 लाख 34 हजार 995 रुपये का ही पारिश्रमिक वितरित किया जा सका है।

वर्ष 2024 में 155 करोड़ का पारिश्रमिक

पिछले साल इन चार जिलों के संग्राहकों को कुल 155 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक दिया गया था। लेकिन इस वर्ष मौसम की मार के कारण यह आंकड़ा काफी नीचे जाने की संभावना है। वन विभाग का अनुमान है कि इस बार संग्राहकों को केवल 65 करोड़ रुपये के आस-पास ही पारिश्रमिक मिल पाएगा।

मौसम की मार से तेंदूपत्ता पर असर

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आंधी, ओले और बेमौसम बारिश के चलते तेंदूपत्तों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर असर पड़ा है। तेंदूपत्ता के कोमल पत्तों पर पानी और ओलों के गिरने से छेद और गांठें बन रही हैं, जिससे वे उपयोग लायक नहीं रह जाते। मुख्य वन संरक्षक आरसी दुग्गा ने स्वयं सुकमा जिले के संग्रहण केन्द्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।

जिलावार संग्रहण स्थिति

बस्तर: 15 लाट में 17201.240 मानक बोरा

दंतेवाड़ा: 11 लाट में 17001.715 मानक बोरा

बीजापुर: 23 लाट में 11598.187 मानक बोरा

सुकमा: 43 लाट में 71198.774 मानक बोरा

ग्रामीणों ने खुद उठाया सड़क निर्माण का बीड़ा तब जगा प्रशासन

शहर सत्ता/बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अंतर्गत ग्राम केशकुतुल की सड़क को ग्रामीणों द्वारा स्वयं के व्यय से निर्माण करने की खबरें मिडिया की सुर्खियां बनते ही हड़कंप मच गया है। जिसे जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम विकास सर्वे एवं जनपद सीईओ पीआर साहू केशकुतुल पहुंचे और गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि केशकुतुल ग्राम पंचायत में 10 पारा टोला है। सभी पारा टोला दूर दूर फैले हुए है, इनमें से ग्राम सुराखेड़ा सहित कुल चार टोला है जहां तक पहुंचने के लिए सड़क और पुल पुलिया नहीं है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को यह भी बताया कि मनरेगा से सड़क नहीं बनने के कारण ग्रामीणों के द्वारा चंदा एकत्रित कर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीणों के लौटाए जायेंगे पैसेः सीईओ पीआर साहू ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि केशकुतुल भैरमगढ़ सड़क के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने सुराखेड़ा में 2 पुलिया निर्माण को स्वीकृति देने की मांग की है। जनपद सीईओ पी. आर. साहू ने ग्राम सुराखेड़ा/ केशकुतुल से भैरमगढ़ तक के सड़क निर्माण करने के लिए ग्रामीणों द्वारा चंदा एकत्रित कर जेसीबी मशीन लगाने में किए गए 50,000 हज़ार रुपये को वापस देने की बात कही है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य लच्छूराम मोडियामी, सरपंच पार्वती कोरसा सहित केशकुतुल के ग्रामीण बडी संख्या में मौजूद थे।

देना था हितग्राहियों को 4 माह का मिला सिर्फ 2 से 3 महीने का चना

शहर सत्ता/सीतापुर। सीतापुर में राशन दुकान संचालक ने पात्र हितग्राहियों को उनके हिस्से का चना देने के बजाए उसे कालाबाजारियों के हवाले कर दिया। वहीं खाद्य विभाग लीपापोती करने में जुटा हुआ है। कमोबेश सीतापुर की तरह ही दूरस्थ अंचलों और ग्रामीण तथा वनवासी क्षेत्रों में शासकीय राशन दुकान से हितग्राहियों को मिलने वाला सरकारी चना घोटाले की भेंट चढ़ता जा रहा है। हितग्राहियों ने चना वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए खाद्य निरीक्षक से शिकायत की थी। हितग्राहियों की शिकायत पर जांच के बजाए खाद्य विभाग मामले की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। खाद्य निरीक्षक ने इस मामले में न कोई जांच की और न ही हितग्राहियों को उनके हिस्से का चना दिला पाई। शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नही होने से हितग्राहियों में आक्रोश व्याप्त है।

अब तक नहीं हुई है कोई जांच

इस बात की भनक लगते ही ग्रामीणों ने चना वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए पखवाड़े भर पहले खाद्य निरीक्षक से शिकायत की थी। ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि अगर राशन दुकान की बारीकी से जांच हो जाये तो कई चौकाने वाले मामले सामने आयेंगे। शिकायत के इतने दिनों बाद भी जांच नही होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अब तक इस मामले की जांच नही होना भी कई सवालों को जन्म देता है। खाद्य निरीक्षक की बातों से ऐसा लगता है कि वो इस मामले की जांच को लेकर उदासिन है। खाद्य विभाग इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करना चाहता है।

छत्तीसगढ़ में खुलेगा मेदांता अस्पताल सीएम से दिल्ली में मिले डॉ त्रेहन

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से दो प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात की। मेदांता अस्पताल के संस्थापक और प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहन ने रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि, वे इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश करना चाहते हैं। यह अस्पताल उन्नत चिकित्सा तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों, रिसर्च और प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा।

सॉफ्ट ड्रिंक्स आधारित संयंत्र का ऑफर

वहीं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने रायपुर में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस आधारित संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें 250 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोज़गार सृजन को गति देगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का थामा स्नेह भरा हाथ

नीति आयोग की बैठक में कुछ यूं मिले हमारे सीएम से पीएम

शहर सत्ता/रायपुर। देश की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान एक आत्मीय क्षण सामने आया, जिसने सबका ध्यान खींचा। लंच ब्रेक के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का हाथ थामते हुए मुस्कराकर कहा कि, छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है। इस एक वाक्य में प्रधानमंत्री का स्नेह, विश्वास और राज्य के प्रति विशेष रुचि झलक रही थी।

यह क्षण किसी औपचारिक संवाद का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध सीएम श्री साय के प्रयासों की सहज स्वीकृति और सराहना का था। नीति आयोग की बैठक में जहां देशभर के राज्यों ने अपने विकास मॉडल प्रस्तुत किए। वहीं छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति ने प्रधानमंत्री की विशेष रुचि और सराहना प्राप्त की। यह स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ अब केवल एक उभरता हुआ राज्य नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला राज्य बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में हो रहे सकारात्मक बदलाव, औद्योगिक निवेश, और 'आत्मनिर्भर बस्तर' की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की सराहना की। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि कैसे बस्तर अब संघर्ष नहीं, संभावना का प्रतीक बन रहा है। जहाँ कभी बंदूकें चलती थीं, वहाँ अब मशीनें, लैपटॉप और स्टार्टअप की चर्चा हो रही है। नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर की स्थापना से लेकर लिथियम ब्लॉक की नीलामी तक छत्तीसगढ़ अब संसाधनों से परिपूर्ण राज्य बनने की ओर अग्रसर है। देश के विकास में छत्तीसगढ़ की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

बेवकूफों से हमदर्दी

एक लेख में कहा गया है, "बैठना नए तरह का धूम्रपान है।" उन दिनों, जब मैं संपादक नहीं हुआ करता था, तब महज चंद रुपये दिहाड़ी का पत्रकार सिर्फ था। साथी सहचर भी थे लेकिन ज्यादातर मेरी सिगरेट के मुफ्त तलबगार थे। पांच रुपट्टी का तंबाखु पाउच खाने वाले भी मेरी 20 रूपये प्रति नग वाली श्वेत डंडिका पर डाका मारने ललहाते थे। बजट का नुकसान और बुराइयां भी खूब झेला। खैर, कुछ इसे आधुनिक स्टाइल मानते हैं और कुछ सोचते हैं "किसे परवाह है।" याद रखिए इसका संबंध दूसरों की राय से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ा है। दुर्भाग्यवश, वे यह नहीं समझते कि वे बैठने की लत के चरम पर पहुंच चुके हैं!

लत, व्यसन और जानलेवा मोड़ तक पहुंच चुके सिगरेट का छल्ला उड़ाने और तंबाखू पाउच की गाढ़ी लाल पीक किसी पिट वाइपर की तरह थूकने वाले बेवकूफों से मेरी हमदर्दी है। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और फ़ूड एंड ड्रग कंट्रोलर्स की खानापूर्ति वाली कार्रवाई से ज्यादा नाराजगी है। छत्तीसगढ़ में सिगरेट, गुटखा, तंबाखु खाने वालों को जितना नुकसान उनका नशा नहीं कर रहा उससे कहीं ज्यादा क्षति नकली, घटिया और स्तरहीन उत्पाद से हो रही है।

प्रतिबंध के बावजूद नकली गुटखा फैक्ट्रियां, डुप्लीकेट पाउच प्रोडक्ट और भाटापारा-तिल्दा ब्रांड सिगरेट धड़ल्ले से करोड़ों का कारोबार बन गए हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब जिम्मेदार जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और अन्य इदारे खामोश बैठे हैं। नकली पनीर की फैक्ट्री और निकोटिन प्रोडक्ट मेरे लिए एक सामान जानलेवा खतरा महसूस होते हैं। बावजूद इसके ऐसे उत्पाद और उत्पादनकर्ताओं की मुश्कें अब तक क्यों नहीं कासी जा रहीं यह अन्वेषण का विषय है।

हर साल 31 मई को मनाया जाने वाला 'वर्ल्ड नो टोबैको डे' तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जनता को जागरूक करता है। मैं भी खुद को रोजाना तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में सजग करते रहता हूं। लेकिन किसी सचमुच की जाहिल कौम की तरह अब भी पढ़ा लिखा गधा ही बना हुआ हूं। इसे शुरू करना आसान है लेकिन छोड़ना मुश्किल। इस आदत को छोड़ दें, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब 'एल्कोहलिक एनोनिमस' की तरह पढ़े-लिखे गधों का संगठन भी कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ जायेंगे।

कोंदा-भैरा के गोठ

-पानी-बादर के दिन आइस तहाँ ले साँप-डेडू मन के घलो दिन आ जाथे जी भैरा.

-हव जी कोंदा.. तहाँ ले चारों मुड़ा ले साँप चाबे के खबर आए लगथे.

-सही आय.. हमर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के तो ए मामला म नागलोक के रूप म प्रसिद्ध हे.

-पहिली इहाँ अइसन बिखहर जीव मन ले बाँचे खातिर 'नगमत' के परंपरा रिहिसे.. नागपंचमी, हरेली या फेर कोनो कोनो गाँव म पोरा परब म मनाए जाय 'नगमत' ल.. एमा माँत्रिक शक्ति के माध्यम ले साँप मन के जहर उतारे के विधि म लोगन ल पारंगत तो करे ही जावय संग म साँप आदि बिखहर जीव मनले पूजा सुमरनी कर बाँचे के अरजी बिनती करे जावय.

-सही आय संगी.. अभी घलो कतकों गाँव मन म 'नगमत' के परंपरा देखे म आथे.. अच्छा तैं जानथस के सबो किसम के साँप मन जहरीला नइ होय.

-अच्छा.. अइसे?

-हव.. हमर देश म 550 किसम के साँप पाए जाथे तेमा के सिरिफ 10 प्रजाति भर मन जहरीला होथें.

-वाह भई..!

-हव.. जानकार मन के कहना हे के जादातर मनखे साँप के जहर ले नहीं भलुक वोकर झझक के सेती मरथें.. तेकर सेती साँप के चाबे म फोकटइहा डर्राय के बलदा वोकर उपचार के उदिम करना चाही.

(२) -बटकी म बासी अउ चुटकी नून.. मैं ह गावत हँव ददरिया तैं कान दे के सुन ओ.. चना के दार..

-का बात हे जी कोंदा.. गरमी म बासी के गजब सेवाद लेवत हस तइसे जनाथे.. तोर डोकरी ह एमा कुछू मोहनी उहनी डार दिए हे तइसे जनावत हे?

-अरे नहीं जी भैरा.. हमन तो बटकी के बारा म नून मढ़ा के ही पेट भर बासी खा लेथन.. फेर मोला ए समझ म नइ आवत हे संगी के पाछू के सरकार ह बासी म अउ का का ना के खाइस होही ते तेमा बासी दिवस म करोड़ों के घोटाला होय रिहिसे कहिके सुनाथे!

-अब बासी म नून.. संग म गोंदली अउ कभू कभार मही नहीं ते दही.. हरियर मिरचा.. चेंच भाजी के साग.. अतके तो सँघरथे जी संगी.. अतकेच म करोड़ों के भ्रष्टाचार कइसे हो सकथे?

-राजनीति म सब संभव हे संगी.. जे मन भुइयाँ म पालथी मारे बइठ के खाइन होहीं ते मन तो सस्ताहा बासी झड़क डारिन होहीं, फेर जे मन टेबल कुर्सी म बइठ के चम्मच म झड़के रिहिन हें.. हो सकथे वोकर मन के बासी के चार्ज ल फाइवस्टार के शैली म जोंगाय होही.

-कोन जनी रे ददा.. मोला तो सुने म ही अकबकासी असन लागत हे.!

पर्यावरण पर 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का अच्छा असर

प्रो.चेतन सिंह सोलंकी

एक राष्ट्र एक चुनाव (ओएनओई) के प्रस्ताव ने पूरे देश में चर्चाओं को जन्म दिया है, जिसमें मुख्य रूप से शासन की दक्षता, लागत-बचत और प्रशासनिक और सुरक्षा प्रणालियों पर बोझ कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसे ऐसे समाधान के रूप में सराहा जा रहा है, जो सरकारी मशीनरी को चुनाव-प्रचार की तुलना में शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बना सकता है। साथ ही जो विभिन्न राज्यों में लगातार चुनावों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम कर सकता है। लेकिन एक और आयाम है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है- इसका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव।

चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनके लिए पर्यावरण को भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर चुनाव चक्र में लोगों की भारी आवाजाही, सामग्री की छपाई, ईंधन की खपत, बिजली का उपयोग और बड़े पैमाने पर शारीरिक और डिजिटल लामबंदी होती है।

28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग आयोजित चुनावों की संख्या से इसका गुणा करें, तो यह पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है। यदि भारत ओएनओई के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराता है तो अनुमान है कि 6.5 लाख करोड़ के कुल अनुमानित चुनाव व्यय में से पांच साल की अवधि में कम से कम 4 या 5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यह केवल वित्तीय बचत नहीं है; यह गतिविधियों में भारी कमी को भी दर्शाता है। ओएनओई के क्रियान्वयन के माध्यम से बचाए जाने वाले उत्सर्जन कई स्रोतों से आएंगे। यात्रा एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

हर चुनाव में लाखों मतदान अधिकारी, अर्धसैनिक बल, राजनीतिक प्रचारक और मतदाता हवाई, रेल और सड़क सहित परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके देश भर में घूमते हैं। कम चुनाव का मतलब है कम यात्राएं, कम ईंधन की खपत और कम प्रदूषण। राजनीतिक अभियान तीव्र ऊर्जा उपयोग का एक और क्षेत्र है।

हजारों रैलियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें लाउडस्पीकर, लाइटिंग सेटअप, डीजल जनरेटर, वाहनों के काफिले और अस्थायी संरचनाओं का उपयोग किया जाता है- ये सभी बिजली और ईंधन पर चलते हैं। इसके अलावा, चुनाव के मौसम में मुद्रित सामग्री- पोस्टर, बैनर, फ्लायर्स, टी-शर्ट और प्लास्टिक के सामान की बाढ़ आ जाती है। इनमें से ज्यादातर एकल-उपयोग वाली वस्तुएं हैं जो या तो लैंडफिल में चली जाती हैं या जला दी जाती हैं, जिससे प्रदूषण में योगदान होता है।

यहां तक कि डिजिटल और प्रसारण अभियान भी पर्यावरणीय लागत वहन करते हैं। हर सोशल मीडिया विज्ञापन और वीडियो स्ट्रीम के पीछे एक डेटा सेंटर होता है, जो हर सेकंड बिजली की खपत करता है। सैकड़ों निर्वाचन क्षेत्रों और कई चुनाव चक्रों में संचयी डिजिटल पदचिह्न काफी बड़ा हो जाता है। ओएनओई इन चक्रों को एकल, समयबद्ध प्रक्रिया में संघनित कर देगा, जिससे बेहतर नियंत्रण, नियोजन और अंततः कम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव संभव होगा।

कार्बन-तीव्रता का मतलब है कि एक इकाई जीडीपी के लिए कितना सीओटू उत्सर्जित होता है। 2023-24 तक भारत की कार्बन-तीव्रता प्रति ₹100 खर्च पर 0.24 किलोग्राम सीओटू थी। इसके आधार पर, ₹5 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप लगभग 1.2 मिलियन टन- या 12 लाख मीट्रिक टन सीओटू उत्सर्जन होगा।

यह लगभग 12 लाख परिपक्व पेड़ों को काटने के बराबर है। क्योकि एक पूर्ण विकसित पेड़ अपने जीवनकाल में लगभग एक मीट्रिक टन सीओटू अवशोषित करता है। ऐसे में ओएनओई के बहुआयामी लाभ हैं। इससे पैसों की बचत होती है और प्रशासनिक तनाव कम होता है। सरकारों को दीर्घकालिक नीति पर काम करने के लिए अधिक निर्बाध समय मिलता है। और यह स्पष्ट रूप से जलवायु-लाभ भी प्रदान करता है।

जलवायु संकट की मांग है कि हम हर गतिविधि को क्लाइमेट के नजरिए से देखें। एक देश एक चुनाव न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बल्कि बिना किसी अतिरिक्त निवेश के कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकता है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

किसी पर रहम, किसी को सजा- ये कैसा 'तंत्र' है!

राजदीप सरदेसाई

कुछ सप्ताह पहले मैंने 'माय नेम इज रहीम खान' शीर्षक से एक वीडियो-ब्लॉग प्रसारित किया था, जिसमें बताया गया था कि आज एक भारतीय मुसलमान होने का क्या मतलब है। इसके बाद तत्काल ही मैं दक्षिणपंथियों के निशाने पर आ गया।

मुझ पर आरोप लगाया गया कि बढ़ते इस्लामिक चरमपंथ की समस्या से बचने के लिए मुस्लिम-विक्टिमहुड का झूठा चित्रण कर रहा हूं। लेकिन आज सोचने पर लगता है कि शायद मेरे उस ब्लॉग का शीर्षक 'माय नेम इज अली खान महमूदाबाद' होना चाहिए था।

फेसबुक पर टिप्पणी के लिए अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी बताती है कि हमारे राजनीतिक-तंत्र में क्या गलत है, जो भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर धकेल रहा है। उनका अपराध यह था कि उन्होंने आपरेशन सिंदूर पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों के पाखंड पर सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा था कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बहुत से दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें इतने ही पुरजोर तरीके से यह मांग भी करनी चाहिए कि मॉब लिंचिंग, बुलडोजर और नफरत फैलाने वाली राजनीति के शिकार होने वाले दूसरे लोगों को भी भारतीय नागरिकों की भांति सुरक्षा मिले। ऐसा लिखकर अली खान यह बताना चाह रहे थे कि कर्नल कुरैशी को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बताने और धरातल पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव के बीच कितना अंतर है। क्या इस टिप्पणी को भारत की स्वायत्तता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली बातों के तौर पर देखा जा सकता है?

या क्या इसे किसी महिला की गरिमा का अपमान करने वाला कृत्य कहा जा सकता है? सरकार की आलोचना कब से इस हद तक एक अपराध हो गई कि भाजपा युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता सरपंच की शिकायत पर तत्काल गिरफ्तारी हो जाए या हरियाणा महिला आयोग नोटिस भेज दे?

महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से जब एक टीवी इंटरव्यू में यह पूछा गया कि अली खान ने किसी महिला की गरिमा का हनन कैसे किया है तो उनके पास इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। यह साफ है कि अन्य 'सरकारी' संस्थानों की तरह महिला आयोग ने भी आधिकारिक निर्देशों पर जल्दबाजी में नोटिस भेज दिया था। इसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल थी।

इस मामले ने कई परेशान करने वाले सवाल खड़े किए हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के लिए सत्ता का दुरुपयोग। यह इस तरह का इकलौता मामला नहीं है। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वह असहमति के स्वरों को दबाने के लिए इसी तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है।

याद करें कि कैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बारे में सोशल मीडिया पर कथित रूप से एक अपमानजनक पोस्ट शेयर करने पर मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले को 2022 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। और कैसे द्रमुक सरकार ने तब चुप्पी साध ली थी, जब एक 'समूह' ने सत्ताधारी पार्टी के मुखर आलोचक और यूट्यूबर सुवुक्कू शंकर के घर में गंदगी फेंक दी थी। और कैसे कोलकाता के एक प्रोफेसर पर ममता बनर्जी का कार्टून फॉरवर्ड करने के आरोप लगाए गए थे और उन्हें गिरफ्तारी के 11 साल बाद जाकर रिहा किया गया था।

एक मायने से भारतीय राजनीतिक तंत्र ने युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के इस कथन को अपना लिया है कि 'बोलने की आजादी तो है, लेकिन बोलने के बाद आजादी की गारंटी नहीं है!'

हालात ऐसे बन गए हैं कि कौन कानून के दायरे में आएगा और कौन नहीं, यह भी आज पूरी तरह से सत्ता-कुलीनों की निजी धारणाओं के अधीन हो गया है। अली खान प्रकरण की तुलना मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह से करें, जिन्होंने कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक और साम्प्रदायिक टिप्पणी की थी।

शाह को मंत्री पद से हटाने या सार्वजनिक रूप से फटकारने के बजाय भाजपा-नेतृत्व इस पर चुप है। मंत्री ने दिखावटी माफी मांग ली है। तब हाईकोर्ट को स्वत: संज्ञान लेकर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर जोर देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की टिप्पणी को 'राष्ट्रीय शर्म' बताया। कोर्ट द्वारा इस मामले में एसआईटी नियुक्त करने के बावजूद पुलिस ने दिल्ली के अली खान मामले की तरह गिरफ्तारी के लिए सक्रियता नहीं दिखाई है। किसी पर रहम और किसी को सजा- क्या यही 'नया भारत' है?

कौन कानून के दायरे में आएगा और कौन नहीं, यह भी आज पूरी तरह से सत्ता-कुलीनों की निजी धारणाओं के अधीन हो गया है। यकीन न हो तो अली खान प्रकरण की तुलना मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह से करके देख लें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

साप्ताहिक शहर सत्ता

ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर

मन की बात के 122वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (25 मई, 2025) को पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और इसे खत्म करना है. उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सेना का मिशन ही नहीं बल्कि ये बदलते भारत की तस्वीर है. पीएम मोदी ने कहा, "आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है. आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसने हर हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया." मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था और इसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत. उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था. इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर नई ऊर्जा दिख रही है." प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है. ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है." इसके अलावा उन्होंने शेरों की आबादी के बारे में भी बात की. पीएम ने कहा, "पिछले 5 साल में गुजरात के गिर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है. शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहजनक है। 11 जिलों में 35 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेरों की जनगणना की गई, जिसके लिए टीमों ने 24 घंटे इन इलाकों की निगरानी की. कुछ दशक पहले गिर में स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव का बीड़ा उठाया. वहां नवीनतम तकनीक के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया."

जातिगत जनगणना की सराहना...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार (25 मई, 2025) को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक हुई. इस बैठक में तीन अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए. बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना की सराहना की गई. इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी सामने आए. प्रधानमंत्री और एनडीए शासित मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के पराक्रम को सैल्यूट किया गया. इस पर लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ. इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना करवाने को लेकर लिए गए फैसले की सराहना करते हुए भी प्रस्ताव पास किया गया. बैठक के दौरान दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने अपने द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों को बुकलेट के तौर पर जानकारी साझा की।

तेज प्रताप यादव 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित

नई दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. रविवार (25 मई, 2025) को लालू ने एक्स पर पर पोस्ट कर लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है.

ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है. अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं. आगे लिखते हैं, "अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी. उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है. अपने निजी जीवन का भला-बुरा और गुण-दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है. उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें. लोकजीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं. परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है. धन्यवाद." आरजेडी सुप्रीमो के इस फैसले की अब लोग सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लालू के निर्णय पर लिखा, "ऐसे ही नहीं लोग लालू जी को मसीहा कहते." दूसरी ओर एक यूजर ने लिखा, "तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव विवाद पर ये बयान दिखाता है कि लालू परिवार अब सार्वजनिक छवि और राजनीतिक मर्यादा को लेकर सख्त रुख अपना रहा है, लेकिन सवाल ये भी है क्या इतना काफी है? क्या तेज प्रताप जैसे जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति के व्यक्तिगत कृत्य का असर सिर्फ निष्कासन से खत्म हो सकता है? जनता अब केवल बयान नहीं, न्याय और पारदर्शिता की उम्मीद करती है." दरअसल तेज प्रताप यादव और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव से जुड़े मामले को लेकर लालू यादव ने यह कार्रवाई की है।

कुवैत ने रातोंरात रद्द कर दी हजारों महिलाओं की नागरिकता

नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह सोकर जागें और आपका बैंक अकाउंट बंद हो गए? आप ऑनलाइन पेमेंट न कर पाएं? आपको हर सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएं? मुस्लिम देश कुवैत में ऐसा ही हुआ. जब उन लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि उनकी नागरिकता ही रद्द कर दी गई है. कुवैत की सरकार ने रातोंरात हजारों लोगों की नागरिकता रद्द कर दी. इस लिस्ट में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं. सरकार उन लोगों की नागरिकता ज्यादा खत्म कर रही है, जिन्हें शादी के बाद यहां की नागरिकता मिली थी. इस लिस्ट में वो महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने कुवैत के पुरुषों से शादी कर नागरिकता हासिल की थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जॉर्डन की रहने वाली एक महिला जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने गई तो पता चला कि उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है. बाद में पता चला कि उनकी नागरिकता छीन ली गई है. दिसंबर 2023 में अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल सबाह कुवैत के अमीर बने थे. इसके बाद उन्होंने संसद को भंग कर दिया और संविधान के कुछ हिस्सों को भी सस्पेंड कर दिया. अब अमीर का कहना है कि केवल उन लोगों को कुवैत की नागरिकता मिल सकती है, जिनका यहां के लोगों के साथ ब्लड रिलेशन है. कुवैत में पहले से भी ऐसे कई लोग रह रहे हैं, जिनके पास वहां की नागरिकता नहीं है. साल 1961 में ब्रिटिश संरक्षण से आजाद होने के बाद करीब 1 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई थी. जिन लोगों के पास नागरिकता होगी, उनको बैंकिंग, शिक्षा, सरकारी नौकरी और अन्य सारी सुविधाएं मिल पाएंगी।

यूनुस ने अमेरिका को बेच दिया बांग्लादेश

नई दिल्ली। बांग्लादेश में सियासी उथल-पुथल के बीच देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाई है और इसमें से कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय बैन लगा हुआ है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि यूनुस ने सत्ता हथियाने के लिए प्रतिबंधित लोगों की मदद ली, जिनसे अब तक हमने बांग्लादेश के लोगों की रक्षा की थी. उन्होंने कहा, "सिर्फ एक आतंकवादी हमले के बाद हमने सख्त कदम उठाए. कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब बांग्लादेश की जेलें खाली हैं. यूनुस ने ऐसे सभी लोगों को रिहा कर दिया और अब बांग्लादेश में उन आतंकवादियों का ही राज है." शेख हसीना ने आगे कहा, "हमारे महान बंगाली राष्ट्र का संविधान जिसे हमने लंबे संघर्ष और मुक्ति संग्राम से हासिल किया है।

हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बदले में आतंकी हमले मिलेः शशि थरूर

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से पाकिस्तान और PoK में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर समर्थन दिलाने की कोशिशें जारी हैं. इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा शुरू किया. प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क के 9/11 स्मारक से की. यह एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक इशारा था जो यह बताता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और उसका जवाब भी वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर देना होगा.

शशि थरूर ने अमेरिका की धरती पर आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बदले में आतंकी हमले मिले. न्यूयॉर्क के भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने कहा कि जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, जबकि उससे कुछ ही हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए थे. हम बार-बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं, लेकिन जवाब में हमें आतंक मिला है. थरूर ने मुंबई हमलों का भी जिक्र किया जिसमें हमलावरों को पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से लाइव निर्देश मिल रहे थे. उन्होंने कहा कि यह सब कुछ पाकिस्तान की राज्य संरक्षित आतंकवाद नीति का स्पष्ट उदाहरण है. शशि थरूर ने अमेरिकी जनता को याद दिलाते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिका ने 'ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर' के तहत ओसामा बिन लादेन को मारा, उसी तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है. उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने ओसामा को पनाह दी।

चीन-इंडिया समेत एशिया के 5 देशों में कोरोना की नई लहर में मिले केस

गाजा। नई दिल्ली। एशिया में कोविड-19 की नई लहर आई है, जिसमें सिंगापुर, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और भारत में मामले बढ़े हैं. भारत में 257 सक्रिय मामले हैं. JN.1 वैरिएंट इसकी वजह है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं. सावधानी बरतें, मास्क पहनें, हाथ धोएं और लक्षण दिखें तो टेस्ट कराएं. कमजोर इम्युनिटी वालों को बूस्टर डोज की सलाह दी जा रही है. एशिया के कई देशों में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं. सिंगापुर, चीन, थाईलैंड, हांगकांग और भारत में नई लहर की खबरें सामने आ रही हैं. भारत में 19 मई 2025 तक 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतनी होगी. क्या है स्थिति और क्या फिर से बूस्टर डोज लेना जरूरी है। सिंगापुर में मई 2025 की शुरुआत में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

PAK बढ़ा रहा एटमी ताकत, चीन बिछा रहा मिलिट्री वेब...

नई दिल्ली। पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) की एक रिपोर्ट सामने आई है. यूएस इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है. अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को दूसरी सुरक्षा चिंता के रूप में देखता है, जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सैन्य जरूरतों के बल पर एक वैश्विक नेता के तौर पर अपने को देखते हैं, जो चीन का मुकाबला कर सकता है. रिपोर्ट में 22 अप्रैल की पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के मिलिट्री टकराव के बारे में भी लिखा गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैन्य ठिकानों को म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए गंभीर सामरिक खतरा बन सकता है, क्योंकि ये देश भारत की सीधी समुद्री और थल सीमाओं के निकट हैं.इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत चीन हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है. इससे भारत की सुरक्षा स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 के मध्य में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पार गोलीबारी और हमलों के बावजूद भारत की रणनीतिक सोच में चीन को प्राथमिक खतरे के रूप में देखा जा रहा है.

अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्तूबर 2024 के अंत में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के दो विवादित इलाकों से सेनाएं पीछे हटाने पर सहमति बनाई. हालांकि, ये सीमावर्ती तनाव को कुछ हद तक कम करता है, लेकिन सीमा विवाद अब भी अनसुलझा है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तेजी से अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है और भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है. ये रणनीति पाकिस्तान की सैन्य सोच और सीमा पर आक्रामकता को बताती है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन की आर्थिक और सैन्य उदारता पर निर्भर है।

कप्तान गिल के सामने 3 बड़ी चुनौतियां

आसान नहीं होगा इंग्लैंड का टेस्ट दौरा

नई दिल्ली। आखिरकार इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है और शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान बन गए हैं. ऋषभ पंत को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. बहुत लंबे समय बाद ऐसा पहली बार होगा जब टीम इंडिया रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना टेस्ट मैच खेल रही होगी. गिल भारत के सबसे युवा टेस्ट कप्तानों में से एक बन गए हैं. यहां आप उन 3 सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में जानिए, जिनका कप्तान शुभमन गिल को सामना करना पड़ सकता है.

1. रोहित शर्मा को रिप्लेस करना मुश्किल

जब विराट कोहली जैसा दिग्गज किसी खिलाड़ी के टैलेंट की तारीफ करे. वहीं भारत के दिग्गज अंपायर अनिल चौधरी भी रोहित के कप्तानी वाले माइंडसेट की खूब तारीफ कर चुके हैं. रोहित की कप्तानी में ही टीम इंडिया 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर आ रही है. उनकी कप्तानी में भारत 2023 WTC फाइनल और 2023 ODI वर्ल्ड कप भी खेल चुका है. इतने शानदार कप्तानी रिकॉर्ड को देखते हुए 25 वर्षीय शुभमन गिल के लिए तुरंत उनकी जगह ले पाना काफी मुश्किल होगा.

2. गिल किस क्रम पर बैटिंग करेंगे

सबसे बड़ा सवाल है कि शुभमन गिल खुद किस क्रम पर बैटिंग करेंगे. चेतेश्वर पुजारा के ड्रॉप होने के बाद वो नंबर-3 पर खेल रहे थे. अब रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद ओपनिंग बल्लेबाजी का स्लॉट खाली हो गया है. गिल ओपनिंग करेंगे या फिर तीसरे क्रम पर बैटिंग करते रहेंगे. इस सवाल का जवाब साई सुदर्शन के रूप में मिल सकता है. गिल नंबर-3 पर बैटिंग जारी रखें और रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर साई सुदर्शन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

3. विराट कोहली की जगह कौन लेगा?

टेस्ट टीम में विराट कोहली के संन्यास से बैटिंग में नंबर-4 का स्लॉट भी खाली हो गया है. केएल राहुल एक विकल्प हो सकते हैं, जो ओपनिंग के साथ-साथ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग का अनुभव रखते हैं. करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हैं और रणजी ट्रॉफी 2024-25 में 9 मैचों में करीब 54 के औसत से 863 रन बनाकर आ रहे हैं. वहीं सरफराज खान भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग का काफी अनुभव रखते हैं.

क्लासेन की आंधी में उड़ा केकेआर

नई दिल्ली। आईपीएल 2025 का 68वां मुकाबला रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच खेला गया. हेनरिक क्लासेन की नाबाद 105 रनों की शतकीय पारी की बदौलत एसआरएच ने इस मुकाबले में 110 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. यह आईपीएल में केकेआर की सबसे बड़ी हार है. एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278/3 का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया. यह आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. टूर्नामेंट में चार सबसे बड़े स्कोर बनाने का श्रेय इसी टीम के नाम है. उसने 2024 में 287/3 और 2025 में आरआर के खिलाफ 286/6 का स्कोर बनाया था. जीत के लिए 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर 18.4 ओवर में 168 रन ही बना सकी. टीम की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (9) और सुनील नारायण (31) ने पारी की शुरुआत की. अच्छी लय में दिख रहे नारायण को जयदेव उनादकट ने बोल्ड किया. तीसरे नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे (15) भी सस्ते में पवेलियन लौटे. इसके बाद क्रमश: अंगकृष रघुवंशी (14), रिंकू सिंह (9) और आंद्रे रसल जल्द ही आउट हो गए. सातवें नंबर पर मनीष पांडेय ने जरूर 37 रन बनाए लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए. इसके बाद रमनदीप सिंह (13) और हर्षित राणा (34) ने कुछ जुझारू पारी खेली और हार का अंतर कम करने की कोशिश की. अंत में वैभव अरोड़ा बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. इस तरह पूरी टीम 18.4 ओवर में 168 रन पर आउट हो गई. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जयदेव उनादकट, एशान मलिंगा और हर्ष दुबे ने तीन-तीन विकेट चटकाए.

पेटीएम को बड़ी राहत, 5,712 करोड़ के नोटिस पर स्टे

नई दिल्ली। पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कंपनी की रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को भेजे गए जीएसटी नोटिस पर रोक लगा दी है. एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, शनिवार, 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पेटीएम की गेमिंग शाखा - फर्स्ट गेम्स को जारी किए गए 5,712 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस पर रोक लगाने की घोषणा की. दरअसल, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की तरफ से अप्रैल में फर्स्ट गेम्स को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था. फर्स्ट गेम ने सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी. अब 23 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है. वन97 कम्युनिकेशंस ने कहा था कि टैक्स का मामला सिर्फ फर्स्ट गेम तक सीमित नहीं है. यह पूरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है. पेटीएम ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है। सभी संबंधित शो कॉज नोटिस पर आगे की कार्यवाही तब तक स्थगित रहेगी।

अनिल अंबानी के लिए रिलायंस पावर ने खोला कुबेर का खजाना

नई दिल्ली। शेयर बाजार में पिछले हफ्ते एक बार फिर अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाले ADAG ग्रुप की कंपनियों ने धमाल मचा दिया. रिलायंस पावर, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. हालांकि इनमें रिलायंस पावर सबसे आगे रहा, इस शेयर में एक दिन में 19 फीसदी की तेजी देखी गई. इस तेजी के कारण निवेशकों में उम्मीदों की लहर दौड़ गई. इसके साथ ही अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या यह उछाल सिर्फ एक झलक है या लंबी रेस की शुरुआत?

शेयरों में आया तूफानी तेजी

शुक्रवार को रिलायंस पावर के शेयर 19 फीसदी उछलकर 53 रुपये तक पहुंच गए, जबकि रिलायंस होम फाइनेंस में 10 फीसदी की तेजी आई और यह 3.64 रुपये पर बंद हुआ. उधर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 10.5 फीसदी उछलकर 313 रुपये तक पहुंच गए.

इस वजह से आ रही तेजी

देखा जाए तो इस तेजी के पीछे दो मुख्य कंपनियां हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर. दोनों कंपनियों ने बीते समय में भारी कर्ज और कमजोर प्रदर्शन का दौर देखा, लेकिन अब इनकी रणनीति, वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाएं बाजार को नया भरोसा दे रही हैं. रिलायंस पावर की बात करें तो वह अब खुद को सिर्फ बिजली उत्पादक नहीं, बल्कि एक प्रमुख री-न्यूएबल एनर्जी प्लेयर के रूप में स्थापित करने में जुटी है. हाल ही में, रिलायंस की सब्सिडियरी NU Suntech ने 25 साल के लिए 930 MW सोलर पावर और 1860 MWh बैटरी स्टोरेज की डील साइन की है।

गिल को कप्तानी का अनुभव नहीं : गावस्कर

नई दिल्ली। सुनील गावस्कर क्रिकेट से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं. उन्होंने रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सरफराज खान को ड्राप किए जाने पर कहा कि पहले भी देखा गया है कि टीम अच्छा नहीं करती तो 13,14,15 नंबर वाले

खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है. इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. पहला टेस्ट 20 जून से शुरू होगा. स्पोर्ट्स तक से बातचीत में सुनील गावस्कर ने माना कि ये एक बोल्ड सिलेक्शन है. टीम में युवा खिलाड़ी हैं और उनके लिए ये दौरा चुनौतियों से भरा होगा. उन्होंने कहा, "ये अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज है. तो आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए, जो अगले 2-3 साल या इससे भी अधिक तक खेले." गावस्कर ने कहा, "मुझे लगता है कि ये एक बोल्ड सिलेक्शन है. इसलिए क्योंकि शुभमन गिल को आपने देखा तो उन्हें कप्तानी का इतना अनुभव नहीं है. फिर भी उनके साथ ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, करुण नायर टेस्ट खेल चुके हैं, ऋषभ पंत भी हैं जो उनके अच्छे दोस्त भी हैं. ये उनकी मदद करेंगे. ये बहुत अच्छी टीम चयन की गई है." गावस्कर ने कहा, "मुझे लगता है कि इस सीरीज में बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर है, गेंदबाजी हमें जीत दिला सकती है।

LIC का नाम हुआ गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज

नई दिल्ली।। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 24 घंटे में सबसे अधिक बीमा पॉलिसी बेचकर अपने नाम नया रिकॉर्ड बना लिया है. एलआईसी ने शनिवार को कहा कि उसने 24 घंटे में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियां बेचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल कर लिया. इस ऐतिहासिक उपलब्धिक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने खुद वेरिफाई किया है. इसी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से 20 जनवरी, 2025 को एलआई के नेटवर्क के शानदार परफॉर्मेंस को सराहा गया है. 20 जनवरी को देशभर में एलआईसी के कुल 4,52,839 एजेंटों 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचकर इस रिकॉर्ड को हासिल किया.

एलआईसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "24 घंटे के भीतर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट प्रोडक्टिविटी के लिए एक नए ग्लोबल बेंचमार्क को स्थापित किया."

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत

नई दिल्ली। जापान को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (World 4th Largest Economy India) बन गया है. शनिवार (24 मई, 2025) को नीति आयोग के सीईओ (CEO) बीवीआर सुब्रमण्यम ने ये जानकारी दी. उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है.

बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, "हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं. आज हम चार हजार डॉलर (4 Trillion Dollar Economy) की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं." उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों का हवाला देते हुए आगे कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान से भी बड़ी हो गई है. भारत ने ये मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है. अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी ही भारत से आगे है. मुझे उम्मीद है कि हम जल्द तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे."

नीति आयोग के सीईओ ने किया बड़ा दावा

नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हम अपनी योजना पर कायम हैं और अलग सब कुछ सही रहता है तो अलगे ढाई-तीन सालों में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत ने ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है, जब US Tariff के चलते दुनियाभर में हलचल है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सके हैं.

बीवीआर सुब्रमण्यम ने टैरिफ और Apple iPhone पर कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति के Apple iPhone पर टैरिफ लगाने से जुड़े एक सवाल पर सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन (Apple iPhone) का निर्माण अमेरिका में ही होगा, न कि भारत में या किसी और जगह पर. आगे टैरिफ क्या होगा, यह अभी कहना मुश्किल है. हालांकि, हम निर्माण के लिए सस्ती जगह जरूर होंगे."

10.75 करोड़ ने आईपीएल में डाली सिर्फ 18 गेंद

नई दिल्ली। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की सीजन 18 में शुरुआत शानदार हुई थी. टीम ने शुरू के 4 मैच लगातार जीते थे, जिसके बाद लगने लगा था कि दिल्ली प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन सकती है. लेकिन इसके बाद तो टीम अंक तालिका में ऊपर-नीचे होती रही, फिर आईपीएल स्थगित होने के बाद मिचेल स्टार्क का स्वदेश लौट जाना दिल्ली के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. दिल्ली ने सीजन का अपना आखिरी मैच शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से जीता. दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए भारत के तेज टी नटराजन को 10 करोड़ 75 लाख रुपये में ख़रीदा था।

छत्तीसगढ़ में मानसून की आहट: यलो अलर्ट जारी

रायपुर | देशभर में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और अब इसकी चपेट में आने वाला अगला राज्य है छत्तीसगढ़। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 5 जून तक मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसको देखते हुए पूरे राज्य में यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

सुबह से छाए बादल, झमाझम बारिश

शनिवार को सुबह से ही रायपुर के आसमान में बादलों का डेरा रहा। दोपहर होते-होते कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाओं और रुक-रुक कर होती बूंदाबांदी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। बारिश के चलते पिछले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

जिला	अधिकतम तापमान (°C)	सामान्य से गिरावट
रायपुर	33°C	-10°C
बिलासपुर	35°C	-8°C
दुर्ग	34°C	-11.2°C
अंबिकापुर	30°C	-7.3°C
जगदलपुर	32°C	-5°C

11 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग ने चेताया है कि बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, राजनांदगांव, गरियाबंद सहित 11 जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और खुले में न निकलने की सलाह दी गई है।

कहाँ-कहाँ हुई बारिश (पिछले 24 घंटे में)

30 मिमी: अंबिकापुर, मोहला, देवभोग

20 मिमी: खरगांव, बेलरगांव, मारी बंगला, देवरी

10 मिमी: भानुप्रतापपुर, कुकरेल, मैनपुर, लटोरी, कोटाडोल

इन जिलों में बारिश की संभावना

भारी बारिश संभावित:
कोरिया, बिलासपुर, कोरबा

हल्की से मध्यम बारिश (गरज-चमक के साथ):
मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, सरगुजा, जशपुर आदि

बारिश के चांस वाले जिले:
कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा

विशेषज्ञ की राय

"मानसून की गति सामान्य से तेज है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है जिससे पूरे राज्य में बारिश बढ़ेगी। लोगों को बिजली गिरने से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।"
डॉ. आर. के. शर्मा, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर:

अब इंजीनियरिंग सिर्फ तकनीक नहीं, संस्कृति और जीवनशैली भी सिखाएगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों की पहचान अब सिर्फ मशीनों और कोडिंग तक सीमित नहीं रहेगी। नया सत्र उनके लिए तकनीकी दक्षता के साथ-साथ सांस्कृतिक और नैतिक समझ की भी नींव रखेगा। राज्य में पहली बार बीटेक कोर्स में श्रीमद्भागवत गीता, प्राचीन गणित, ज्योतिष और भारतीय संस्कृति को बाकायदा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। "तकनीक के साथ संस्कार"—यही है छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग का नया विज़न, जो 2025-26 सत्र से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में झलकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ बेहतर इंजीनियर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे युवा गढ़ना है जो भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़े हों, नैतिकता को समझते हों और नागरिकता के दायित्व को निभा सकें।

चार नए विषयों से बदलेगा तकनीकी शिक्षा का चेहरा:

फाउंडेशन कोर्स ऑफ एंसिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम – जिसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों की खोजें पढ़ाई जाएंगी।

श्रीमद्भगवतगीता – मैनुअल ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स – एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन की दिशा समझाने वाला पाठ्यक्रम।

इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज साइंस एंड प्रैक्टिसेस – एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान।

इंडियन कल्चर एंड कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया – स्थापत्य कला से लेकर संविधान तक की समझ।

इंजीनियरिंग में अब स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात:

मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम: एक साल में सर्टिफिकेट, दो साल में डिप्लोमा, और चार साल में डिग्री।

ब्रांच-विशिष्ट फिजिक्स: अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार अलग-अलग फिजिक्स पढ़ाई जाएगी।

स्किल-आधारित सब्जेक्ट: जैसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आदि हर वर्ष में शामिल किए जाएंगे।

भविष्य का इंजीनियर – भारतीय आत्मा, वैश्विक सोच

इस बदलाव के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकलने वाले छात्र न केवल तकनीकी दक्ष होंगे बल्कि भारतीय सभ्यता, मूल्य और विज्ञान की परंपरा को भी समझेंगे। यह प्रयोग न केवल शिक्षा प्रणाली को भारतीयता से जोड़ने का प्रयास है, बल्कि नई शिक्षा नीति की आत्मा को भी जमीन पर उतारने का एक बड़ा कदम है।

छत्तीसगढ़ में EWS आरक्षण नहीं हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर। राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को आदेश दिए जाने की मांग की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है.

पुष्पराज सिंह एवं अन्य ने अधिवक्ता योगेश चंद्र के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सवर्ण तबके के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने हेतु 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। जिसके लिए भारत के संविधान में 12 जनवरी 2019 को संशोधन किया गया। जिसके अनुसार सरकारी नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थानों में सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थानों में यह लागू हो गया है, पर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं हुआ है। जिसे लागू करने हेतु याचिका में मांग की गई है। रिट पिटीशन में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण अन्य राज्यों में लागू किया गया है तथा सार्वजनिक

रोजगार में 10% आरक्षण दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में यद्यपि छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश –2019 पाली लागू किया जा चुका है पर अब तक दस प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

12 जनवरी 2019 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में किए गए संशोधन में राज्य सरकार को ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10% आरक्षण देने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है। 19 जनवरी 2019 को भारत संघ में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद चार सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी अध्यादेश तथा लोक सेवा संशोधन अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया था।

किसान तुलाराम चंद्राकर की कहानी बनी मिसाल

47 साल की जिद और जल संघर्ष की जीत के करीब

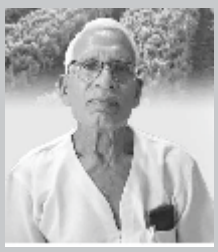

महासमुंद | विशेष प्रतिनिधि

झलप क्षेत्र के एक किसान की 47 वर्षों की अथक मेहनत अब रंग लाने वाली है। 72 वर्षीय तुलाराम चंद्राकर, जो कभी झलप के सरपंच बने थे, आज हजारों किसानों के लिए उम्मीद का चेहरा बन गए हैं। उनका जीवन एक मिशन बन चुका है—अपने इलाके को पानी दिलाने का मिशन। और अब, जब पैरी-सिकासेर नहर लिंक परियोजना का सर्वे पूरा हो चुका है, तो उनके इस लंबे संघर्ष को सफलता मिलती नजर आ रही है।

पानी के लिए जीवन भर की जद्दोजहद

तुलाराम चंद्राकर ने 1978 में सरपंच बनने के बाद इलाके की सबसे बड़ी समस्या—सिंचाई के पानी—को अपना एजेंडा बनाया। झलप क्षेत्र में डेम, नदी, जलाशय जैसी कोई स्थायी जलस्रोत व्यवस्था नहीं है। किसान वर्षा पर या गहरे बोरवेल पर निर्भर हैं, जहां अब जलस्तर 700-800 फीट तक चला गया है।

समिति से सामूहिक संघर्ष तक

तुलाराम ने केवल खुद कोशिश नहीं की, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों को एकजुट किया। उन्होंने "पैरी सिखासेर नहर सिंचाई समिति" बनाई, जिसमें समाज के लोगों ने आर्थिक योगदान भी दिया। साहू समाज से 5,000 रुपये की सहायता मिली और दर्जनों गांवों से किसानों ने 100-100 रुपये देकर समिति के खाते में योगदान दिया।

जन-भागीदारी से बनी आंदोलन की ताकत

तुलाराम और उनकी समिति ने शासन-प्रशासन से संपर्क बनाए रखा। सर्वसमाज समन्वय महासभा के जरिए उन्होंने नेताओं से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे और सार्वजनिक बैठकों में आवाज उठाई। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में सिकासेर-कोडार नहर लिंक योजना को "मोदी की गारंटी" के रूप में शामिल किया गया।

अब उम्मीद के साथ बढ़ते कदम

इस परियोजना का सर्वे पूरा हो चुका है और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तुलाराम को विश्वास है कि उनका सपना जल्द साकार होगा और झलप क्षेत्र के 70 से ज्यादा गांवों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। किसान खेमराज बघेल भी कहते हैं, "पानी के बिना हमारा जीवन शून्य है, लेकिन अब आशा की किरण दिखाई दे रही है।"

सिर्फ योजना नहीं, बदलाव की कहानी

तुलाराम का संघर्ष यह बताता है कि बदलाव केवल नीतियों से नहीं, बल्कि जमीनी जज्बे और जनभागीदारी से आता है। उन्होंने यह दिखाया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले, तो पूरा समाज साथ चलता है और इतिहास बदलता है।

"बुजुर्गों ने रास्ता दिखाया, हमने उसे पकड़े रखा। अब वो सपना हकीकत बनने जा रहा है," — तुलाराम चंद्राकर, किसान।

स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य में कोविड-19 पूरी तरह नियंत्रण में, घबराये नहीं

कोविड-19 से निपटने सचिव कटारिया और आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला ने दिए निर्देश

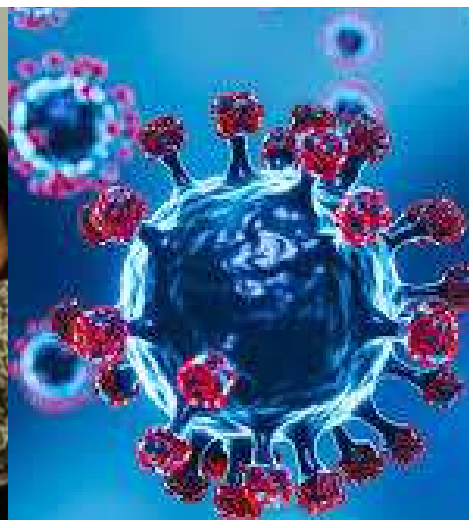

शहर सत्ता/रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिलों में इन्फ्लूएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का सर्वेलेन्स को सुदृढ़ करने हेतु सभी जिलों के जिला सर्वेलेन्स अधिकारियों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई । स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया के निर्देशानुसार तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में आने वाले ऐसे मरीज जिन्हें सर्दी खाँसी, बुखार अथवा गले में खराश होने पर समुचित देखभाल किया जाए।

एकीकृत रोग निगरानी के दिशा निर्देश अनुसार एसएआरआई (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन) मरीजों को चिकित्सक की सलाह पर भर्ती किया जाए । जिलों में सामान्य इन्फ्लूएंजा वाले लक्षणों के मरीजों के इलाज हेतु जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस दौरान जिला रायपुर में एक व्यक्ति को कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है , यह मरीज नियमित स्वास्थ्य निगरानी की प्रक्रिया में है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभाग के सभी अधिकारियों को इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों की सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में ऐसे वायरस जनित रोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग की की सभी तैयारियां पूरी हैं, कोविड केसेस के आने पर बेड भी आरक्षित हैं, इसके लिए दवाइयां और मैन पावर भी पर्याप्त है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के ले तैयार है।

श्री जायसवाल ने ये भी कहा है कि सभी लोगों से अपील की जाती है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नही है। ज्ञात हो कि हाल ही में भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेस की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बात सामने आई है कि देश में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो माइल्ड हैं जिसमें अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है।

तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने की समीक्षा

कोविड-19 केस की संभावित स्थितियों को लेकर तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में ओपीडी, वार्ड एवं उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी है। इसमें डॉक्टरों तथा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी, दवाओं की उपलब्धता, आक्सीजन, बेड की व्यवस्था तथा ओपीडी के संचालन की सम्बन्ध में चर्चा हुई है। यहां कोरोना के संभावित प्रकरणों से निपटने के लिए अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है। सामान्य ओपीडी से अलग कोविड -19 ओपीडी की व्यवस्था की गई है। संभावित गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार प्रदान करने के लिए अलग से एंट्री पॉइंट बनाया गया है। इन क्षेत्रों की पहचान के लिए साईनएज बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अस्पताल में कोविड -19 के लिए स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है।

मंत्री दयालदास ने किया ई-हियरिंग का शुभारंभ, प्रकरणों का होगा तेजी से निदान

उपभोक्ता अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रख सकेंगे अपना पक्ष

शहर सत्ता/रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज पंडरी स्थित राज्य उपभोक्ता फोरम कार्यालय में ई-हियरिंग का शुभारंभ किया। अब कोई भी उपभोक्ता कहीं से भी वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ई-हियरिंग में अपना पक्ष रख सकेंगे। ई-हियरिंग शुरू होने से उपभोक्ताओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आज रायपुर जिले से चरणबद्ध रूप में शुभारंभ की गई है। आगामी महीनों में प्रदेश के ई-हियरिंग का विस्तार करते हुए 17 जिलो में करने जा रहे हैं।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई-हियरिंग के माध्यम से उपभोक्ता मामलों का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा साथ ही ई-हियरिंग से लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ई-हियरिंग से नागरिकों और वकीलों को न्यायालयों तक पहुंचना आसान होगा। ई-हियरिंग से उपभोक्ता मामलों को जल्दी से हल किया जा सकेगा जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय प्राप्त होगा। मंत्री ने कहा कि ई-हियरिंग से अदालतों के बुनियादी ढाचों पर खर्च कम होता है। ई-हियरिंग से प्रकरणों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है जिससे परदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर शर्मा, बार कौन्सिल रायपुर के अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी सहित अधिवक्तागण शामिल थे।

एसीएस पिंगुआ की अपील; रोड सेफ्टी में सबकी सहभागिता जरुरी

शहर सत्ता/रायपुर। अपर मुख्य सचिव (गृह) श्री मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसीएस श्री पिंगुआ ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों का सबकी सहभागिता से बेहतर क्रियान्वयन हो। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात को बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास किया जाए। एसीएस श्री पिंगुआ ने सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सड़कों में मिलने वाली ग्रामीण सड़कों के जंक्शन, दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों/ब्लैक स्पॉट्स में प्राथमिकता से आवश्यक सुधारात्मक उपाय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने दी हादसों की जानकारी

प्रदेश में पिछले चार महिनों में 5322 सड़क दुर्घटनाओं में 2591 व्यक्ति की मृत्यु एवं 4825 घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सचिव एस प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2019-2025 तक चिन्हाकित/लंबित ब्लैक स्पॉट्स में से 69 तथा 101 जंक्शन सुधार किया गया है। यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा 3 लाख 06 हजार 106 प्रकरणों में 11.92 करोड़ रूपए तथा परिवहन विभाग द्वारा 2 लाख 80 हजार 568 प्रकरणों में 58.35 करोड़ रूपए की शमन शुल्क वसूल किए गए है।

'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल का विशेष उल्लेख

दंतेवाड़ा की शिक्षा क्रांति पर पीएम मोदी ने जताई प्रसन्नता

दंतेवाड़ा | विशेष संवाददाता

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजी बोर्ड) की परीक्षा में दंतेवाड़ा जिले की ऐतिहासिक सफलता ने देशभर का ध्यान आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम के 122वें संस्करण में दंतेवाड़ा की इस उपलब्धि का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इसे "शैक्षणिक नवजागरण की मिसाल" बताया। पीएम मोदी ने कहा, "दंतेवाड़ा की धरती ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प मजबूत हो और रणनीति सशक्त हो, तो कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा की रोशनी फैलाई जा सकती है।" उन्होंने कहा कि जिस ज़िले को कभी माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था, अब वही ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

बोर्ड परीक्षा में उल्लेखनीय प्रदर्शन

दंतेवाड़ा जिले ने वर्ष 2025 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 95 प्रतिशत सफलता दर के साथ पूरे राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं, 12वीं की परीक्षा में भी जिले ने छत्तीसगढ़ राज्य में छठा स्थान अर्जित किया है। यह परिणाम न केवल शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों की सफलता भी है।

विज्ञान और खेलों में भी चमक

प्रधानमंत्री ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब की स्थापना और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "इन इलाकों के बच्चों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि है और वे खेलों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।"

शिक्षा के माध्यम से बदलाव

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह परिवर्तन केवल शैक्षणिक सफलता नहीं, बल्कि सामूहिक जागरूकता, आत्मविश्वास और बदलाव की एक समग्र यात्रा है। "जहां कभी विद्यालय जाने से पहले सुरक्षा की चिंता होती थी, वहीं अब वही गांव राज्य के टॉपर्स दे रहे हैं," उन्होंने जोड़ा।

सरकार और समाज का समन्वय

पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में शिक्षा को केंद्र में रखकर जो कार्य हो रहे हैं, वे साहस, नीति और परिवर्तन का प्रतीक हैं।

उन्होंने विशेष रूप से राज्य के प्रशासनिक नेतृत्व की प्रशंसा की और इस अभियान को 'संघर्ष से सफलता की यात्रा' बताया।

'रॉकी' छालीवुड के नेपोलियन

- कमाई के साथ काम आई बचत बढ़ा आत्मविश्वास
- भाड़ा नहीं देने पर मालिक ने सामान सड़क पर फेंका था
- किराये में कॉमिक्स और फ़िल्मी मैगजीन से पैसे कमाए

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

रायपुर। महज 5'5 फुट का छरहरा लड़का, एक छोटे से कस्बे से खाली हाथ बड़े ख्वाब लेकर राजधानी रायपुर पहुंचा। न पैसा था, न अनुभव, न नौकरी—सिर्फ अध्ययनशीलता और कर्मठता ही साथ थी। इन्हें छॉलीवुड इंडस्ट्री का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संघर्षों से तपकर यह शख्स आज सफल बिजनेसमैन और फिल्म फाइनेंसर बन चुका है। बात हो रही है गरियाबंद से रायपुर आए रॉकी दासवानी की।

शुरुआत गांव से : गरियाबंद—एक मिट्टी की खुशबू से भरा गाँव, वहीं रॉकी का जन्म और बचपन बीता। पढ़ने का शौक बचपन से था, बारहवीं में गणित विषय के साथ अच्छे अंक लाए, लेकिन उन्हें पाठ्यक्रम से ज़्यादा साहित्यिक व ज्ञानवर्धक किताबें पसंद थीं। 12 साल की उम्र में कॉमिक्स किराए पर देना शुरू किया। पहली कमाई हुई—2 रुपये। धीरे-धीरे 3000-5000 किताबों का संग्रह बन गया।

संघर्ष के दिन : रायपुर आने के बाद शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। 300-400 रुपये किराये के कमरे में सिर्फ एक सूटकेस, पुराना पंखा और गद्दा। भूखे दिन, उधारी पर खाना, और मकान मालिक द्वारा सामान सड़क पर फेंके जाने जैसी घटनाएं आम थीं। ऐसे में संजय भैया नाम के जानने वाले ने सहारा दिया। S.T.D. बूथ में रात को बैठना और तीन कुर्सियों जोड़कर वहीं सो जाना—ऐसे बीते कई दिन।

रॉकी-सतीश की जोड़ी क्यों खास? : "मैं उनकी रचनात्मकता में हस्तक्षेप नहीं करता था, उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी। वहीं मैं व्यावसायिक पक्ष संभालता। क्रिएटिव विज़न और प्रैक्टिकल सोच के इस संतुलन ने हमें मजबूत टीम बना दिया।"

बॉलीवुड का अनुभव : "बॉलीवुड एक सपना है—जो मैंने भी देखा और कोशिश की। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी जो भी मुझसे कुछ सीखना चाहता है, मैं तैयार हूँ।"

सामाजिक और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ : "मैं समय का प्रबंधन करता हूँ—सेहत, परिवार, समाज, व्यापार सबको बराबरी से समय देता हूँ। मेरे लिए क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती है। हर तीन-चार साल में एक फिल्म बनती है, लेकिन पूरी निष्ठा से।"

गरियाबंद से रायपुर तक का सफर : "खोने को कुछ नहीं था, सिर्फ संघर्ष था। हर दिन खुद को साबित करना था। यही मेरी असली पढ़ाई थी—ज़िंदगी की पढ़ाई।"

भरोसे पर राय : "भरोसा टूटना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने तोड़ा, लेकिन कुछ ने संभाला भी। भरोसे से ही रिश्ते बनते हैं, और ज़िंदगी खूबसूरत बनती है।"

कौन-कौन बने सहारा? : "शुरुआत में चाचा राजो रासवानी के पास रहा। उन्होंने अकाउंट का काम सिखाया। धीरे-धीरे एक भरोसेमंद दोस्ती का दायरा बना। लेकिन असली सहारा मेरी किताबें रहीं, जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया।"

युवाओं के लिए संदेश : "बड़ा सोचिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। लगन से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।"

रॉकी की पसंद

निर्देशक: सतीश जैन, प्रेम चंद्राकर, मनोज वर्मा, मनीष मानिकपुरी, मृत्युंजय, शांतनु पाटनवार

अभिनेता: अनुज शर्मा, प्रकाश अवस्थी, कारण खान, अमलेश नागेश, दीपक साहू

अभिनेत्री: शिखा चिताम्बरे, एलसा घोष, अनिकृति चौहान, काजल सोनबेर, दीक्षा जायसवाल

चरित्र कलाकार: पुष्पेंद्र ठाकुर, संजय महानन्द, पूरन किरी, अनिल शर्मा, मनमोहन ठाकुर, अंजलि चौहान, उपासना वैष्णव

कपड़ों से नहीं, सोच से होती है इंसान की पहचान"

शहरसात्ता/रायपुर। मॉडलिंग इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली राखी मण्डल आज सिर्फ रैम्प वॉक तक सीमित नहीं, बल्कि एक सोच, एक प्रेरणा बन चुकी हैं। 2018-19 में ओरिफ्लेम जैसे बड़े ब्रांड से करियर की शुरुआत करने वाली राखी मण्डल ने ना सिर्फ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, बल्कि बार-बार जजमेंट और आलोचना का सामना भी डटकर किया। खासकर जब अपने ही 'सो-कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स' और समाज के कुछ नेता उनके कपड़ों को 'बेशर्मी' से जोड़ते हैं, तो वह साफ कहती हैं, ये हमारे कपड़ों की नहीं, आपकी सोच की बात है।

मॉडलिंग इंडस्ट्री की चमक के पीछे कई बार फ्रॉड ऑफर, मानसिक तनाव, बॉडी शेमिंग और आत्म-संघर्ष की सच्चाई छुपी होती है। बहुत बार मुझे 'माचिस की तिल्ली' कहा गया, और उस दौर में मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी,वह बताती हैं। लेकिन उनका विश्वास, आत्मबल और आध्यात्मिक जुड़ाव उन्हें वापस खड़ा करता है। मैं सेल्फ-मोटिवेटेड हूं। मेरी सबसे बड़ी ताक़त यही है कि मैं खुद को बार-बार उठाती हूं। राखी नए मॉडल्स को सलाह देती है की,फाइनेंसियली इंडिपेंडेंट बनिए। एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। मॉडलिंग में आने से पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में निवेश ज़रूरी है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का इरादा नहीं रखतीं, लेकिन राखी का मानना है कि अगर कोई इंसान उनकी वजह से मुस्कुरा रहा है, तो वही उनके लिए असली सफलता है। सक्सेस मेरे लिए बस इतनी है की मेरी वजह से किसी एक शख्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए, तो मैं सफल हूं।"

रामलीला के लक्ष्मण से "गिरधारी" तक स्टारडम का सफर

शहर सत्ता/रायपुर। छइयां भुइंया के 'गिरधारी' यानि की छत्तीसगढ़ के असली माटी पुत्र ठाकुर मनमोहन सिंह बचपन में गाँव की रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभाया करते थे। लोगों की तालियों और तारीफों ने उनके अंदर एक कलाकार को जन्म दिया। धीरे-धीरे लोग कहने लगे हीरो जैसा दिखता है तू,और यही बात दिल में उतर गई। इसी उम्मीद के साथ निकल पड़े सपनों की नगरी मुंबई की ओर। लेकिन मुंबई में सपने जितने बड़े थे, संघर्ष उससे भी महाकाय निकला। तीन साल तक लगातार मेहनत, ऑडिशन, रिजेक्शन और मायूसियों के बाद हारकर वापस गाँव लौटना पड़ा। लगा सब खत्म हो गया। फिर एक दिन मौका मिला फिल्म छइहा भुइया में खलनायक 'गिरधारी' का किरदार। इस रोल ने न सिर्फ गाँव बल्कि शहर तक में तहलका मचा दिया। लोग उनका असली नाम भूल गए और 'गिरधारी' के नाम से पहचानने लगे। आज भी मनमोहन को लोग उसी नाम से पुकारते हैं, मनमोहन उर्फ गिरधारी।"

संघर्ष और सिद्धांत की कहानी

विलन होते हुए भी मैंने फिल्में छांट कर की। मनमोहन ने यह साबित कर दिया कि एक अभिनेता का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्होंने कभी 'हीरो-हीरोइन की मर्जी' वाली फिल्मों में घुसपैठ नहीं की, बल्कि खुद के टैलेंट पर विश्वास रखा। कोई ताकत मुझे बिजी नहीं देखना चाहती थी। ये लाइन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में छिपी हुई राजनीति की गहराई तक झांकती है। एक कलाकार के संघर्ष को दबाने की कोशिशें हर कोने में दिखीं। निजी रिश्ते, गलतफहमियाँ और टूटता विश्वास भी सहा हूं।

रिश्ते में आई दरार, पर हद में किया विरोध

लेकिन हर रिश्ते में दरार किसी एक घटना से नहीं, बल्कि राजनीति और आर्थिक खेलों से आती है। मेकअप लगा था, डांस कर रहा था, लेकिन अचानक एल्बम से हटा दिया गया। एक कलाकार के आत्मसम्मान को झकझोरने वाला अनुभव। मनमोहन ने प्रतिक्रिया में बाल और दाढ़ी तक मुंडवा दी — ये केवल लुक चेंज नहीं, एक मानसिक विद्रोह था। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सियासी खौफ का आलम है। यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है, वैसी असल राजनीति में भी नहीं होती। मनमोहन की यह टिप्पणी इंडस्ट्री में पनपते अहंकार और गुटबाज़ी पर सीधा वार है। यूनियन बनाकर क्या करोगे, जब कलाकार ही अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। यह सिस्टम नहीं, कलाकारों की निष्क्रियता पर सवाल है।

खलनायक बना फिर भी निर्विवाद रहा

मनमोहन का इंडस्ट्रीज में गुटबाजी, प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव को लेकर स्पष्ट लेकिन सटीक संदेश है। उनका मानना है कि जो भी मतभेद हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कलाकार आप जैसे लोगों से सीखते हैं। यह कथन विनम्रता, अनुभव और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। एक सच्चा कलाकार वही है, जो तमाम विवादों के बीच भी गरिमा बनाए रखे। मनमोहन की कहानी केवल एक कलाकार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो संघर्ष करता है, टूटता है, मगर सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। "गिरधारी" बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाई, और मनमोहन बनकर सिनेमा में अपनी सच्ची पहचान कायम रखी।

खुद पर था यकीन इसलिए पीछे नहीं हटीं

शहरसात्ता/रायपुर। छोटे शहर से बड़ी सोच लेकर निकली डिंपल ठाकुर ने मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाया, बल्कि समाज की सीमित सोच और मानसिक दबावों को भी पीछे छोड़ा। पहले से खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर चुकीं डिंपल जानती थीं कि जीतने पर उन्हें न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिलेगा, बल्कि परिवार का भी वह अपनापन, जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी।

शुरुआती संदेह से आत्मविश्वास तक

फ्रेशर के रूप में उन्हें फैसलों पर संदेह हुआ, लेकिन अनुभवों और लोगों के सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ता गया। जज बनने के बाद भी उन्होंने खुद को 'सीखने वाला' ही माना।

नए मॉडल्स के लिए तीन मंत्र:

1. माता-पिता का साथ सबसे अहम
2. एक लक्ष्य पर फोकस, दिशा न बदलें
3. क्वालिटी पर ध्यान, अलग करना ज़रूरी है

सच्ची सफलता क्या है?

डिंपल के लिए सफलता सिर्फ खिताब या पैसा नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, जो उन्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। डिंपल की कहानी बताती है कि अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो हर मंच आपका है,चाहे वो रैंप हो या ज़िंदगी।

झीरम हादसे की 12वीं बरसी कांग्रेस भाजपा ने दी श्रद्धांजलि

रायपुर। झीरम नरसंहार की 12वीं बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने राजीव भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित अन्य कांग्रेस नेता शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया गया।

भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार ने इस नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, लेकिन केंद्र की एनआईए ने जांच को रोकने का प्रयास किया। एनआईए ने पीड़ितों से कोई पूछताछ नहीं की और संदिग्ध नक्सलियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। एनआईए की जांच रोकने की कोशिशों के बावजूद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसआईटी जांच के मार्ग को साफ किया। हालांकि, राज्य में सरकार बदल जाने के कारण जांच पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे झीरम नरसंहार की जांच में बाधा डाल रहे हैं ताकि सच्चाई न सामने आए।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि झीरम नरसंहार कांग्रेस के लिए एक ऐसा गहरा घाव है जो कभी नहीं भरेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया और कहा कि यह एक साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह घटना देश के लोकतंत्र के लिए एक कलंक है। श्रद्धांजली सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

झीरम नरसंहार पर प्रमुख नेताओं के बयान

सुरक्षा क्यों हटाई गई

छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा घोर नक्सल इलाके में क्यों हटाई गई थी। यह भाजपा की तत्कालीन सरकार की एक बड़ी चूक या फिर सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है। झीरम नरसंहार कांग्रेस के लिए वह घाव है जो कभी नहीं भर सकता। यह घटना लोकतंत्र के माथे पर लगा एक कलंक है। कांग्रेस पार्टी इस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और जितनी भी बाधाएं आएं, उनका डटकर मुकाबला करेगी।

एनआईए जांच में सेंध

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने एसआईटी बनाकर झीरम नरसंहार की जांच शुरू की, क्योंकि एनआईए ने पीड़ितों से पूछताछ तक नहीं की थी। एनआईए ने 2015 के बाद जांच बंद कर दी थी, बावजूद इसके जब एसआईटी बनी, तब भी एनआईए ने जांच में बाधा डाली। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज कर दी, जिससे एसआईटी की जांच का रास्ता खुला, लेकिन केंद्र सरकार अब तक जांच में बाधा डाल रही है। भाजपा सरकारें झीरम की सच्चाई छिपाने की कोशिश करती रही हैं। 12 सालों के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। भाजपा के नेताओं को झीरम का सच उजागर होने से डर लगता है।

राजनीतिक साजिश

झीरम नरसंहार कोई नक्सली हमला नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। मैं इस यात्रा का प्रभारी था, लेकिन एनआईए ने मेरा बयान तक नहीं लिया। हमलावर पूछ रहे थे कि नंद कुमार पटेल कौन है, जो दर्शाता है कि यह हमला राजनीतिक मकसद से किया गया। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल हैं – दो दिन भरपूर सुरक्षा के बाद तीसरे दिन अचानक सुरक्षा क्यों हटाई गई, यह आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। मैंने इस मसले को कई बार सार्वजनिक किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी बात की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह हमला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को रोकने के लिए किया गया था।

अपूरणीय क्षति

आज का दिन कांग्रेस के लिए अत्यंत दुखद है क्योंकि हमने झीरम में अपने कई नेताओं को खोया। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा क्यों हटाई गई। यह भाजपा सरकार की चूक या साजिश हो सकती है। झीरम कांग्रेस के लिए वह घाव है जो कभी नहीं भर सकता। यह घटना लोकतंत्र के लिए एक कलंक है जिसे मिटाया नहीं जा सकता।

नरसंहार पर कांग्रेस का सवाल

- 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा के दौरान ज़ेड प्लस सुरक्षा वाले नेताओं के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात किया गया?
- नक्सलियों की हिटलिस्ट में शामिल महेंद्र कर्मा की हत्या की योजना के बारे में सूचनाएं इंटेलिजेंस तक पहुंचीं, पर बस्तर और सुकमा के एसपी को क्यों नहीं दी गईं?
- महेंद्र कर्मा को जेड प्लस सुरक्षा या एनएसजी कमांडो क्यों नहीं दिए गए जबकि नक्सलियों का उनपर हमला पहले भी हो चुका था?
- सुकमा कलेक्टर के किडनैप मामले में सरकार ने नक्सलियों से क्या डील की, इस पर आज तक छत्तीसगढ़ जनता को कोई जानकारी नहीं मिली।
- नंदकुमार पटेल पर पहले भी नक्सली हमला हो चुका था, फिर भी उन्हें जेड प्लस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई?
- परिवर्तन यात्रा से पहले पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा का आश्वासन दिया था, फिर सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई?
- सारकेगुड़ा नरसंहार के बाद बड़े अधिकारी सुरक्षा में शामिल थे, लेकिन परिवर्तन यात्रा में कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं था?
- रोड ओपनिंग गाड़ी के बिना झीरम यात्रा क्यों कराई गई जबकि पिछली घटनाओं में यह जरूरी थी?
- विकास यात्रा में हजारों जवान तैनात थे, लेकिन परिवर्तन यात्रा को केवल 125 जवानों की सुरक्षा क्यों दी गई?
- सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा क्यों नहीं की गई जबकि बड़ी संख्या में सशस्त्र बल मौजूद थे?
- 25 मई 2013 को झीरम नरसंहार के बाद घायल नेताओं को तुरंत चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिली?
- नक्सलियों द्वारा सिर्फ नंदकुमार पटेल और उनके पुत्र की हत्या और उनकी सामग्री लूटना इस घटना को सामान्य नक्सली हमला नहीं बनाता।
- झीरम घटना से पहले दिनेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी जिससे सत्ता में बैठे लोगों को खतरा था।
- बस्तर में कांग्रेस की मजबूत पकड़ और नेताओं के सक्रिय कार्यों से भाजपा सरकार चिंतित थी।
- पूर्व आईपीएस ने बताया था कि झीरम घाटी की डील 60 करोड़ रुपए की हुई थी, पर इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई?
- रमन सिंह ने कहा था कि झीरम घाटी बहुत संवेदनशील है, फिर भी परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों रखी गई?

झीरम घाटी पहुंचे भाजपाध्यक्ष: 12वीं बरसी पर शहीद नेताओं को दी श्रद्धांजलि

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव और भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दरभा जनपद पंचायत के झीरम घटनास्थल पहुंच शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 12 वर्ष पूर्व 25 मई 2013 झीरम में माओवादियों द्वारा हमले में तत्कालीन शीर्ष नेतागणों एवं सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुई थी। रविवार झीरम धटना स्थल पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक देव ने दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा - किरण देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहा कि, बस्तर डबल इंजन सरकार की नेतृत्व में धीरे-धीरे नक्सली मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह से नक्सली मुक्त हो इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार कार्य कर रहे हैं। बस्तर में शांति स्थापित हो इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बस्तर जल्द ही एक समृद्ध सशक्त और आकर्षक बस्तर के रूप में जाना जाएगा।

ऑपरेशन संकल्प सफल, लाल आतंक ख़त्म...

प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दृढ़ता और फ़ोर्स के ऊंचे मनोबल से लाल आतंक से मुक्त हुई ऐतिहासिक वेदम गुफा

विकास यादव/मुख्य संवाददाता

शहर सत्ता/रायपुर। जहां 2014 में 35 जिले नक्सली गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, वहीं 2025 तक यह संख्या घटकर मात्र 6 जिलों तक सीमित रह गई है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के चलते नक्सली हिंसा में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इस ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 'नक्सल फ्री भारत' के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के कुर्रगुट्टालू पहाड़ (केजीएच) पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। गृह मंत्री ने कहा कि जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ बड़ा एक्शनकुर्रगुट्टालू पहाड़ पीएलजीए बटालियन 1, डीकेएसजेडसी, टीएससी और सीआरसी जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ-साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। उन्होंने बताया कि नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में एक भी जानहानि नहीं हुई। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बधाई देता हूं। पूरे देश को आप पर गर्व है।

नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प शाह ने दोहराते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सलमुक्त हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के सहयोग से अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। कर्रेगुट्टा जैसी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्रवाई सुरक्षा बलों की सतर्कता और साहस का प्रमाण है।

ऑपरेशन की चुनौतियां, जवानों की बहादुरी

करीब 20 हजार जवानों ने 21 दिनों तक इस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन चलाया। पहाड़ी की भौगोलिक कठिनाइयों, खड़ी ढालों और भारी IED खतरे के बीच जवानों ने साहस के साथ कई बार मुठभेड़ की। इस दौरान 450 से अधिक आईईडी निष्क्रिय किए गए। 18 जवान घायल हुए लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी।

हथियारों और संसाधनों की जबरदस्त बरामदगी

इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इनमें इंसास, बीजीएल, मेगा स्नाइपर, एसएलआर, 450 से अधिक आईईडी, विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, 818 बीजीएल सेल, 899 कारडेक्स बंडल शामिल हैं। नक्सलियों के हथियार निर्माण फैक्ट्री और अस्पताल को भी तबाह कर दिया गया। साथ ही 12,000 किलो से अधिक राशन भी जब्त किया गया, जिससे उनकी लंबे समय तक रहने की योजना विफल हुई।

नक्सली बैकफुट पर दिया शांति वार्ता का प्रस्ताव

इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने पांचवां पर्चा जारी कर युद्ध विराम और शांति वार्ता की मांग की। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे नक्सलियों की कमजोरी का संकेत मानते हैं, जो शांति की दिशा में सकारात्मक संकेत है।

प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को नक्सलवाद समाप्ति की दिशा में निर्णायक कदम बताया और प्रभावित क्षेत्रों में विकास की प्रतिबद्धता जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टा को नक्सलियों का यूनिफाइड हेडक्वार्टर बताया और कहा कि अब वहां तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य को दोहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि लाल आतंक के विरुद्ध यह निर्णायक लड़ाई जारी रहेगी और जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा।

2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प

सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में कर्रेगुट्टा जैसे गढ़ों पर किए गए सफल ऑपरेशन इस लक्ष्य को पाने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह लगातार इस अभियान को तेज करने और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की सफलता और नक्सलियों के मनोबल में आई कमी से यह उम्मीद और मजबूत हुई है कि आने वाले वर्षों में देश के अंतःवर्ती हिस्सों से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

करेंगुट्टा की दुर्गमता और नक्सलियों की रणनीति

करीब 60 किलोमीटर लंबी और तीन राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना से घिरी कर्रेगुट्टा पहाड़ी को माओवादी नक्सलियों ने अपना सबसे सुरक्षित गढ़ माना था। यह क्षेत्र अपनी दुर्गमता और चारों तरफ लगाए गए सैकड़ों इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) की वजह से सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण था। नक्सलियों ने यहां हथियारों, विस्फोटकों, राशन के अलावा इलाज के लिए एक अस्पताल भी बना रखा था, जिससे उनकी पकड़ मजबूत बनी रहती थी।

बसवराजू की मौत फ़ोर्स की बड़ी कामयाबी

इस अभियान के दौरान माओवादी कमांडर बसवराजू, जो नक्सलियों के मध्य एक प्रभावशाली नेता था, मुठभेड़ में मारा गया। बसवराजू के मारे जाने से माओवादी संगठनों में भारी संकट पैदा हुआ है। सुरक्षा बलों ने बताया कि बसवराजू के नेतृत्व में नक्सली कई बड़े हमले और आपराधिक गतिविधियां करते थे, इसलिए उसकी मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है।

CRPF DG और CGDGP बोले हम कामयाब

नक्सलियों का गढ़ कर्रेगुट्टा पहाड़ी को नक्सल मुक्त कराने के लिए सुरक्षाबलों ने 21 अप्रैल को नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। इसमें सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के करीब 20 हजार जवानों को लगाया गया था। यह ऑपरेशन बाद 11 मई को बंद कर दिया गया। इस ऑपरेशन की सफलता के बारे में बुधवार को बीजापुर में सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी अरुण देव गौतम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस बारे में एनबीटी ने मंगलवार को ही बताया था कि इस ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए। इनमें 16 महिलाएं शामिल थी।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-22683361, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी।